देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित
www.page3news.in
नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 307 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...कमजोरी झेल रही अर्थव्यवस्था

देहरादून, शनिवार, 18 जनवरी 2020

पेज थ्री

मौसम अधिकतम 16.0° न्यूनतम 6.0°

41945.37

2 अब तक जारी है पाक की परमाणु चोरी

7 रोहित शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रेकॉर्ड

संक्षिप्त समाचार

75 हजार घूस लेते यूपीसीएल का जेई विजीलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा

संवाददाता देहरादून। विजीलैंस की टीम नें एक शिकायत के आधार पर 75 हज़ार की घूस लेते यूपीसीएल के जेई मनीष कुमार को सेलाकुई से गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता नें विजीलैंस टीम को बताया कि उसने अपने घर के विधुत कनेक्शन हेतू विधुत वितरण उपखण्ड़ सेलाकुई कार्यलय में आवेदन किया था जहा जेई मनीष कुमार नें कनेक्शन एंव पोल लगाने के एवज मे शिकायतकर्ता से 85000 हजार रूपये की मांग की जिस पर शिकायतकर्ता ने जेई से पैसे कम करने को कहा तो 75000 हजार रूपये में डील हो गई इस पर विजीलैंस टीम द्वारा सभी आरोपो की गोपनीय जांच की गई जांच में शिकायतकर्ता के आरोप सही पाये गये।

सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर

संवाददाता देहरादून। पुलिस महानिदेशक अनिल के रतूड़ी की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागर में जनपदीय सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल एवं सोशल मीडिया सेल के कार्यों की समीक्षा की गयी एवं सेल में नियुक्त कर्मियों की कार्यदक्षता बढ़ाने एवं जनता में साईबर जागरुकता बढ़ाये जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। अशोक कुमार ने बताया की जनपदो में स्थापित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर राष्ट्र विरोधी, साम्प्रदायिक एवं फेक न्यूज पोस्ट करके अफवाह फैलाने वाले, शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले पर नजर रखी जा रही है। ऐसा करने वालो पर कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

इमरान बेचौन, कश्मीर पर उन्हें कोई सुन नहीं रहा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)
बॉन (जर्मनी)। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को स्वीकारा कि कश्मीर मुद्दे पर उन्हें वैश्विक समुदाय का साथ नहीं मिल रहा। इस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया बेहद धीमी रही है।

निर्भया: नया डेथ वॉरंट जारी

अब 1 फरवरी को फांसी पर लटकाए जाएंगे चारों दोषी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वॉरंट जारी किया है। उन्हें अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उन्हें पहले 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दोषी ने दया याचिका दायर की थी और उसकी दया याचिका खारिज होने के बाद प्रक्रिया के तहत नया डेथ वॉरंट जारी करना पड़ा और फांसी की तारीख बढ़ानी पड़ी।

उधर, डेथ वॉरंट जारी होने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि जब तक फांसी नहीं दे दी जाती उन्हें शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने कोर्ट के बाहर मीडियाकर्मियों से कहा, जो मुजरिम चाहते थे वही हो रहा है...तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारा

■एक दोषी ने दया की अपील की थी जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया

सिस्टम ऐसा हो कि जहां दोषियों की सुनी जाती है।

इससे पहले तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने शुक्रवार को कोर्ट में दोषियों के खिलाफ मौत की सजा पर फिर से डेथ वॉरंट जारी करने की अपील की थी। अडिशनल सेशन जज जस्टिस सतीश कुमार अरोड़ा ने जेल प्रशासन से कहा कि वह अदालत को शाम 4.30 बजे तक यह बताएं कि निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह को यह सूचित किया गया है या नहीं कि राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका अस्वीकार कर दी है। दरअसल, अभियोजन पक्ष के वकील इरफान अहमद ने अदालत को बताया कि मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को अस्वीकार कर दी है।

कोर्ट ने कहा, अगर आप सभी दोषियों द्वारा दया याचिका का विकल्प इस्तेमाल किए जाने तक कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर आपके नियम खराब हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने भी (नियम बनाते वक्त) दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। व्यवस्था कैंसर से ग्रस्त है। बता दें कि 23 साल की पैरामेडिकल की स्टूडेंट निर्भया के साथ 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में सामूहिक रेप किया गया था और निर्ममतापूर्वक मारपीट की गई थी।

जब एचसी ने कहा, व्यवस्था बन गया कैंसर

अदालत मामले में मौत की सजा पाए मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उसने फांसी देने के लिए तय 22 जनवरी की तारीख टालने का अनुरोध किया था। बता दें कि बुधवार को दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि एक दोषी ने दया याचिका दायर की है और अगर उसकी याचिका खारिज होती है तो नियम के तहत फिर नया डेथ वॉरंट जारी करना पड़ेगा। इस पर अदालत ने लताड़ लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन ने एक ऐसी कैंसर ग्रस्त व्यवस्था की रचना की है जिसका फायदा मौत की सजा पाए अपराधी उठाने में लगे हैं।

पंजाब ने भी सीएए के खिलाफ पास किया प्रस्ताव

हमने कुछ बदलावों का ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेजा: कैप्टन अमरिंदर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

चंडीगढ़। केरल विधानसभा के बाद अब पंजाब विधानसभा ने भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। सीएए को निरस्त करने के संबंध में विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इस कानून को विभाजनकारी और देश के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ बताया है। ब्रह्म मोहिंद्रा ने इस प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, 'संसद की ओर से पारित सीएए के चलते देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और इससे लोगों में काफी गुस्सा है। इस कानून के खिलाफ पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हुए जोकि शांतिपूर्ण थे और इसमें समाज के सभी तबके के लोगों ने हिस्सा लिया था।' इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

केरल के बाद दूसरा राज्य बना पंजाब: आपको बता दें कि केरल के बाद पंजाब दूसरा राज्य है, जहां सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि नागरिकता पर संशोधित कानून धर्मनिरपेक्षता के उस ताने–बाने को नकारता है, जिस पर भारत का संविधान आधारित है। इसमें कहा गया, यह विभाजनकारी है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध है, जिसमें प्रत्येक के लिए समानता की बात निहित है। नागरिकता देने में धर्म आधारित भेदभाव के अलावा, ऐसा भी संदेह है कि सीएए हमारे कुछ लोगों की भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए भी खतरा है।

पहले जैसी ही होगी जनगणना

सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, श्हमने एक ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें कुछ बदलावों की बात की गई है। इन बदलावों के बाद सीएए सबको मंजूर हो सकता है। जनगणना अभी हो रहा है और यह पहले जैसी ही होगी। हर किसी की गिनती होगी, चाहे वह मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई और।

देविंदर को चुप कराने एनआईए को जांच का जिम्मा: राहुल गांधी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। जम्मू–कश्मीर पुलिस के ऐंटी–हाइजैकिंग सेल के डीएसपी रहे देविंदर सिंह का केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। राहुल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस गंभीर मामले पर लीपापोती करने में जुटी है। राहुल ने एनआईए की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि इस जांच एंजेंसी के प्रमुख भी एक मोदी ही हैं।

वाईके मोदी की देखरेख में जांच पर आपत्ति: राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, आतंकवादी डीएसपी देविंदर को चुप कराने का सर्वोत्तम तरीका है केस को एनआईए के हाथों सौंप देना।श उन्होंने कहा कि वर्तमान एनआईए प्रमुख के अधीन इस केस की जांच का कुछ नतीजा नहीं आने वाला। राहुल ने कहा, श्एनआईए के प्रमुख भी दूसरे मोदी ही हैं– वाईके जिन्होंने गुजरात दंगों और हरेन पांड्या की हत्या मामले की जांच की थी। वाईके की देखरेख में यह केस खत्म होने जैसा है। बहरहाल, बता दें कि एनआईए के मौजूदा प्रमुख का नाम वाईसी (योगेश चंद्र) मोदी है, न वाईके मोदी।

दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने अब उसी एनआईए पर सवाल उठाया है जिसे कांग्रेस की यूपीए सरकार ने गठित किया था।

आरोप

■आखिर देविंदर को कौन चुप कराना चाहता है और क्यों?

राहुल का सवाल, देविंदर को कौन चुप कराना चाहता है?
आखिर में राहुल ने सवाल किया कि आखिर टेररिस्ट देविंदर को कौन चुप कराना चाहता है और क्यों? उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा, आतंकवादी देविंदर को कौन लोग चुप कराना चाहते हैं और क्यों? राहुल पहले भी देविंदर सिंह के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठा चुके हैं।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

बीजेपी ने घोषित किए दिल्ली के उम्मीदवार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 11 प्रत्याशी एससी वर्ग से हैं और 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज

57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

तिवारी ने नामों की घोषणा करते हुए कहा कि बाकी बचे सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। उन्होंने दावा कि किया बीजेपी इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नामों की घोषणा करते हुए कहा कि गुरुवार को अमित शाह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 57 उम्मीदवारों के नामों पर फैसला हुआ। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अभी नई दिल्ली सिटी से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आम आदमी पार्टी पहले ही 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है।